



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

---

शिमला, मंगलवार, 22 सितम्बर, 2009 / 31 भाद्रपद, 1931

---

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 सितम्बर, 2009

**संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-20/2009-लेज.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-9-2009 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 19) को वर्ष 2009 के अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,  
(अवतार चन्द डोगरा),  
सचिव।

## हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2009

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 17 सितम्बर, 2009 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 12) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

**1. संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 है ।

**2. धारा 7 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2005 (2005 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “मूल अधिनियम” निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 7 में, द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह और कि ईट भट्टा स्वामी के सिवाय कोई भी रजिस्ट्रीकृत व्यौहारी, जो विक्रय के लिए या विक्रय के लिए किसी भी प्रकार के माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में प्रयोग के लिए, किसी माल का आयात करता है, तो वह इस धारा के अधीन उपधारणात्मक कर का संदाय करने का हकदार नहीं होगा।” ।

**3. धारा 10 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 10 में “तीस दिन” शब्दों के स्थान पर “दस दिन” शब्द रखे जाएंगे ।

**4. धारा 11 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 11 में —

(क) उपधारा (4) के खण्ड (ख) में “ से अन्यथा” शब्दों से पूर्व “द्वारा” शब्द अन्तःस्थापित किया जाएगा।;

(ख) उपधारा (5) में विद्यमान परन्तुक का लोप किया जाएगा।; और

(ग) उपधारा (15) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(16) यदि कोई व्यौहारी, अपनी विवरणी में आगत कर प्रत्यय का मिथ्या दावा करता है या आगत कर प्रत्यय जिसका वह हकदार नहीं है प्राप्त करता है, या अपनी विवरणी में कर की उस रकम जो संदत्त नहीं की गई है या वास्तव में संदत्त नहीं की गई थी की बाबत आगत कर प्रत्यय का दावा करता है तो आयुक्त या निर्धारण प्राधिकारी ऐसे व्यौहारी को, उसके द्वारा संदेय कर और ब्याज के अतिरिक्त, ऐसे दावों या प्रत्यय की रकम से दुगुनी राशि के बराबर रकम, शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश देगा।” ।

**5. धारा 14 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 14 में उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“(7) यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर मिथ्या रजिस्ट्रीकरण नम्बर का प्रयोग करता है या इस अधिनियम के अधीन कर का अपवंचन करने के आशय से किसी अन्य व्यक्ति का रजिस्ट्रीकरण नम्बर का प्रयोग

करता है, तो आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति या व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, उसे उस कर के अतिरिक्त जिसके लिए उसका निर्धारण किया गया है या वह निर्धारण के लिए दायी है, अपवंचित कर की रकम या जिसका अपवंचन करने का प्रयास किया गया है के बराबर की रकम, शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश दे सकेगा ।” ।

**6. धारा 15 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 15 में उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु प्रतिभूति, दस हजार रूपए से कम नहीं होगी, किन्तु एक वर्ष के लिए अनुमानित कर के दायित्व से अधिक नहीं होगी ।” ।

**7. धारा 16 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 16 में:—

(क) उपधारा (6) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(6-क) यदि कोई व्यौहारी विहित तारीख तक बिना किसी पर्याप्त हेतुक के विवरणी तैयार करने में असफल रहता है, तो वह शास्ति के रूप में पांच हजार रूपए की राशि संदत्त करने के लिए दायी होगा ।” ;

(ख) उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(7) यदि व्यौहारी पर्याप्त हेतुक के बिना, उपधारा (4) के उपबन्धों की अपेक्षाओं का पालन करने में असफल रहता है, तो आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसे व्यौहारी को, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उस कर की रकम जिसके लिए उसका निर्धारण किया गया है या जिसके निर्धारण के लिए वह दायी है के अतिरिक्त, कर की रकम जिसके लिए उसका निर्धारण किया गया है या धारा 21 के अधीन जिसके निर्धारण के लिए वह दायी है के—

(i) दस प्रतिशत के बराबर, पन्द्रह दिन तक के विलम्ब के लिए;

(ii) पच्चीस प्रतिशत के बराबर, पन्द्रह दिन से अधिक, किन्तु तीस दिन से अनधिक विलम्ब के लिए; और

(iii) पचास प्रतिशत के बराबर, तीस दिन से अधिक विलम्ब के लिए;

की रकम शास्ति के रूप में देने के निदेश दे सकेगा ।” ; और

(ग) उपधारा (8) में “ऐसी रकम जो पच्चीस प्रतिशत से कम नहीं होगी किन्तु जो कर की रकम से डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी जिसके लिए उसका निर्धारण किया जाता है” शब्दों के स्थान पर “कर की रकम, जिसके लिए उसका निर्धारण किया गया है या निर्धारण किए जाने के लिए दायी है, की दुगुनी के बराबर रकम” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

**8. धारा 17 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (4) में “ऐसी उपधारा (1) के अधीन कटौती योग्य कर की रकम के दुगुने से अनधिक राशि के रूप में संदत्त करेगा” शब्दों, कोष्ठक और अंक के स्थान पर “वह उपधारा (1) के अधीन कटौती योग्य कर की रकम के बराबर राशि, शास्ति के रूप में संदत्त करेगा ” शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

**9. धारा 19 का संशोधन.**—मूल अधिनियम के अंग्रेजी पाठ में, धारा 19 की उपधारा (2) में “as the case any be” शब्दों के स्थान पर “as the case may be” शब्द रखे जाएंगे ।

**10. धारा 20 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (3) में “से अनधिक” शब्दों के स्थान पर “की” शब्द रखा जाएगा ।

**11. धारा 21 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(क) उपधारा (1) के स्पष्टीकरण के भाग (1) में “अक्तूबर” शब्द के स्थान पर “दिसम्बर” शब्द रखा जाएगा।;

(ख) उपधारा (7) में “यह निदेश कर सकेगा कि व्यौहारी इस प्रकार निर्धारित रकम के अतिरिक्त ऐसी राशि जो पन्द्रह प्रतिशत से अन्यून होगी, किन्तु जो उस रकम के डेढ़ गुणा से अधिक नहीं होगी, शास्ति के रूप में संदत्त करेगा” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “यह निदेश करेगा कि व्यौहारी निर्धारित कर की रकम के अतिरिक्त, इस प्रकार निर्धारित कर की रकम के बराबर की राशि, शास्ति के रूप में संदत्त करेगा” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।; और

(ग) मूल अधिनियम के अंग्रेजी पाठ में उपधारा (9) में शब्द “therefore” के स्थान पर “therefor” शब्द रखा जाएगा ।

**12. धारा 28 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में “शास्ति की किसी रकम का,” शब्दों और चिन्ह के पश्चात् “दायित्व के अन्तिम अवधारण के पश्चात्,” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे ।

**13. धारा 30 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 30 में,—

(क) उपधारा (3) के खण्ड (घ) में “विक्रय” शब्द का लोप किया जाएगा।; और

(ख) उपधारा 16 में “पांच हजार रुपए तक की हो सकेगी” शब्दों के स्थान पर “दो हजार रुपए होगी” शब्द रखे जाएंगे, और तत्पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(17) यदि कोई व्यौहारी मिथ्या बीजक जारी करता है या प्राप्त करता है और बीजक को मिथ्या जानते हुए उस का प्रयोग करता है, तो आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उस कर के अतिरिक्त जिसके लिए उसका निर्धारण किया गया है या वह निर्धारण किए जाने के लिए दायी है, शास्ति के रूप में पांच हजार रुपए की रकम के बराबर की रकम या ऐसे बीजक में अन्तर्वलित कर की रकम से दुगुनी रकम, जो भी अधिक हो, संदत्त करने का निदेश दे सकेगा।”।

**14. धारा 33 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 33 की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(3) व्यौहारी इस अधिनियम के अधीन कर के संदाय के दायित्व के अभिनिश्चय के प्रारम्भ से, उसके कारबार की बाबत सत्य, शुद्ध और पूर्ण सूचना प्रकट करने के लिए आबद्ध होगा और यदि वह बिना किसी पर्याप्त हेतुक के ऐसी सूचना देने में असफल रहता है या उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अधिकारी को मिथ्या या अशुद्ध सूचना देता है या क्रय या विक्रय की किन्हीं विशिष्टियों को छिपाता है, तो आयुक्त या धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उसकी सहायता करने के लिए नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसे व्यौहारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, उसे कर की रकम जिसके लिए उसका निर्धारण किया गया है या निर्धारित किए जाने के लिए दायी है, के पच्चीस प्रतिशत के बराबर की राशि शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश दे सकेगा।”।

**15. धारा 34 का संशोधन.—**मूल अधिनियम की धारा 34 में,—

(क) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“(2—क) राज्य की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं में प्रवेश करने वाले या राज्य की राज्य क्षेत्रीय सीमाओं से बाहर निकलने वाले माल यान या जलयान का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, इस धारा के प्रयोजनों के लिए, केवल निकटम चैक पोस्ट या बैरियर से ही गुजरेगा, ऐसा न करने पर ऐसा स्वामी या भारसाधक व्यक्ति, इस धारा के लिए उपबन्धित किसी अन्य शास्ति के अतिरिक्त, माल के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर या दस हजार रुपए, जो भी अधिक हो, शास्ति संदत्त करने के लिए दायी होगा।” ;

(ख) उपधारा (4) में,—

(i) प्रथम परन्तुक में “पच्चीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, किन्तु जो माल के मूल्य से पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी” शब्दों और चिन्ह के स्थान पर “पचास प्रतिशत के बराबर होगी,” शब्द और चिन्ह रखे जाएंगे।; और

(ii) द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु यह और कि जहां ऐसे यान द्वारा वहन किया गया माल, राज्य में उसके प्रवेश के पश्चात्, किसी यान या वाहन द्वारा राज्य से बाहर वाहित किया जाता है, तो यान या जलयान के स्वामी या भारसाधक व्यक्ति पर यह साबित करने का भार होगा कि माल वास्तव में राज्य से बाहर गया है।”;

(ग) उपधारा (6) में, “ऐसी रकम के लिए जो माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत से अधिक न हो किन्तु जो माल के मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं होगी, विहित प्ररूप और रीति में, प्रतिभूति सहित या रहित, उसकी तुष्टि की प्रतिभूति देने या बन्ध पत्र निष्पादित करने” शब्दों और चिन्हों के स्थान पर “उसकी तुष्टि की प्रतिभूति माल के मूल्य के पच्चीस प्रतिशत के बराबर नकद या बैंक गारण्टी या बैंक ड्राफ्ट के रूप में देने” शब्द रखे जाएंगे। ;

(घ) उपधारा (7) में “से अनधिक किन्तु जो माल के मूल्य के पन्द्रह प्रतिशत से कम नहीं” शब्दों के स्थान पर “के बराबर” शब्द रखे जाएंगे।; और

(ङ) उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“(12) जहां मालयान या जलयान का कोई प्रभारी व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर जो उपधारा (2) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट चैक पोस्ट या बैरियर के भारसाधक अधिकारी या किसी अन्य अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो माल का परेषण करने वाले या माल के परेषिती की बाबत उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है या माल का वहन बिना दस्तावेजों के या वास्तविक दस्तावेजों के बिना करता है, तो अधिकारी, जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो, ऐसे भारसाधक व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसे माल के मूल्य के दस प्रतिशत के बराबर की रकम शास्ति के रूप में संदत्त करने का निदेश देगा।” ।

**धारा 44 का संशोधन.—**मूल अधिनियम की धारा 44 में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम द्वारा या के अधीन, अधिकरण को प्रदत्त कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए अध्यक्ष से गठित एक अपीलीय अधिकरण की स्थापना करेगी।

(1-क) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन, अधिकरण को प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन के लिए अधिकरण के लिए उतने सदस्य, जितने यह उचित समझे, नियुक्त कर सकेगी । ”;

(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(5) अधिकरण के समक्ष लाए गए समस्त मामले, विहित की गई प्रक्रिया के अनुसार विनिश्चित किए जाएंगे । ”; और

(ग) उपधारा (8) में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

“परन्तु अधिकरण के समक्ष राज्य के मामलों का प्रतिनिधित्व, ऐसे अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो आबकारी एवं कराधान अधिकारी या विधि अधिकारी की पंक्ति से नीचे का न हो।” ।

### AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 14 of 2009

## THE HIMACHAL PRADESH VALUE ADDED TAX (AMENDMENT) ACT, 2009

(As Assented to by the Governor on 17th September, 2009)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (Act No. 12 of 2005).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows: —

**1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Value Added Tax (Amendment) Act, 2009.

**2. Amendment of section 7.**— In section 7 of the Himachal Pradesh Value Added Tax Act, 2005 (12 of 2005) (hereinafter referred to as the ‘principal Act’), for second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided further that no registered dealer, except a brick-kiln owner, who imports goods for sale or use in manufacturing or processing any goods for sale, shall be entitled to make payment of presumptive tax under this section.”.

**3. Amendment of section 10.**— In section 10 of the principal Act, for the words “thirty days”, the words “ten days” shall be substituted.

**4. Amendment of section 11.**— In section 11 of the principal Act—

(a) in sub-section (4), in clause (b), after the word “otherwise”, the word “than” shall be inserted.;

(b) in sub-section (5), the existing proviso shall be omitted.; and

(c) after sub-section (15), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(16) If a dealer falsely claims input-tax credit in his return or avails input tax credit to which he is not entitled or claims in his return input tax credit in respect of the amount of tax which has not been or was not actually paid, the Commissioner or the Assessing Authority shall direct such dealer to pay, by way of penalty, in addition to the tax and interest payable by him, a sum equal to twice the amount of such claim or credit.”.

**5. Amendment of section 14.**—In section 14 of the principal Act, after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(7) If any person knowingly uses a false registration number or uses a registration number of another person with a view to evade tax under this Act, the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 may, after affording such person or the dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, in addition to the tax to which he is assessed or is liable to be assessed, an amount equal to the amount of tax evaded or attempted to be evaded.”.

**6. Amendment of section 15.**— In section 15 of the principal Act, after sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that the security shall not be less than ten thousand rupees but not exceeding the estimated tax liability for one year.”.

**7. Amendment of section 16.**— In section 16 of the principal Act—

(a) after sub-section (6), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(6-A) If a dealer fails without sufficient cause to furnish annual return by the prescribed date, he shall be liable to pay, by way of penalty, a sum of Rs. 5000/-.”;

(b) for sub-section (7), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(7) If a dealer fails without sufficient cause to comply with the requirements of the provisions of sub-section (4), the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 may, after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, a sum—

(i) equal to ten percentum, for the delay upto fifteen days,

(ii) equal to twenty five percentum, for the delay exceeding fifteen days but not exceeding thirty days, and

(iii) equal to fifty percentum, for the delay exceeding thirty days, of the amount of tax to which he is assessed or is liable to be assessed under section 21, in addition to the amount of tax to which he is assessed or is liable to be assessed.”; and

- (c) in sub-section (8), for the words and signs “which shall not be less than twenty-five percentum, but which shall not exceed one and a half times of the amount of tax to which he is assessed”, the words “equal to twice the amount of tax to which he is assessed or is liable to be assessed” shall be substituted.

**8. Amendment of section 17.**—In section 17 of the principal Act, in sub-section (4), for the words, brackets and figure “not exceeding twice the amount of tax deductible under sub-section (1)”, the words, signs, brackets and figure “equal to the amount of tax deductible under sub-section (1),” shall be substituted.

**9. Amendment of section 19.**— In section 19 of the principal Act, in sub-section (2), for the words “as the case any be”, the words “as the case may be” shall be substituted.

**10. Amendment of section 20.**—In section 20 of the principal Act, in sub-section (3), for the words “not exceeding”, the word “of” shall be substituted.

**11. Amendment of section 21.**—In section 21 of the principal Act—

- (a) in sub-section (1), in the Explanation, in part (i), for the word “October”, the word “December” shall be substituted.;
- (b) in sub-section (7), for the words and signs “may direct that the dealer shall pay by way of penalty, in addition to the amount so assessed, a sum which shall not be less than fifteen percentum, but which shall not exceed one and a half times that amount”, the words and signs “shall direct that the dealer shall pay by way of penalty, in addition to the amount of tax assessed, a sum equal to the amount of tax so assessed” shall be substituted.; and
- (c) in sub-section (9), for the word “therefore”, the word “therefor” shall be substituted.

**12. Amendment of section 28.**—In section 28 of the principal Act, in sub-section (1), after the words and sign “prescribed manner,”, the words and signs “after final determination of liability,” shall be inserted.

**13. Amendment of section 30.**—In section 30 of the principal Act—

- (a) in sub-section (3), in clause (d), the words “the sale is” shall be omitted.; and
- (b) in sub-section (16), for the words “ which may extend to five thousand rupees”, the words “of two thousand rupees” shall be substituted, and thereafter, the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(17) If any dealer issues a false invoice or receives and uses an invoice knowing to be false, the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 may, after affording such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, in addition to the tax to which he is assessed or is liable to be assessed, an amount equal to five thousand rupees or double the amount of tax involved in such invoice, whichever is greater.”.



**14. Amendment of section 33.**—In section 33 of the principal Act, after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(3) The dealer shall be bound to disclose true, correct and complete information of his business regarding ascertainment of commencement of liability to pay tax under this Act and if he fails without sufficient cause to furnish such information or furnishes false or incorrect information to the officer specified under sub-section (1), or conceals any particulars of sales or purchases, the Commissioner or any person appointed to assist him under sub-section (1) of section 3 may, after giving such dealer a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, a sum equal to twenty five percentum of the amount of tax to which he is assessed or is liable to be assessed.”.

**15. Amendment of section 34.**— In section 34 of the principal Act—

(a) after sub-section (2), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(2-A) The owner or the person-in-charge of a goods vehicle or vessel entering the territorial limits of the State or leaving the territorial limits of the State, shall, for the purposes of this section, pass through only the nearest check post or barrier, failing which such owner or person-in-charge shall be liable to pay a penalty, equal to ten percentum of the value of goods or ten thousand rupees whichever is greater, in addition to any other penalty provided for in this section.”;

(b) in sub-section (4)—

(i) in the first proviso, for the words “not exceeding twenty-five percentum of the value of the goods but which shall not be less than fifteen percentum”, the words “equal to fifty percentum” shall be substituted.; and

(ii) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that where the goods carried by such vehicle are, after their entry into the State, transported outside the State by any other vehicle or conveyance, the burden of proving that the goods have actually moved out of the State, shall be on the owner or person-in-charge of the vehicle or vessel.”;

(c) in sub-section (6), for the words and signs “or executing a bond with or without surities for securing the amount of tax, in the prescribed form and manner, for an amount not exceeding twenty-five percentum of the value of the goods but which shall not be less than fifteen percentum of the value of the goods”, the words and signs “in the form of cash or bank guarantee or bank draft, equal to twenty-five percentum of the value of the goods” shall be substituted.;

(d) in sub-section (7), for the words “not exceeding twenty five percentum of the value of the goods but which shall not be less than fifteen percentum of the value of the goods”, the words “equal to twenty-five percentum of the value of the goods” shall be substituted.; and

(e) after sub-section(11), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(12) Where any person-in-charge of goods carriage or vessel fails to give information as required under sub-section (2) about the consignor or consignee of the goods, within such time as may be required by the officer-in-charge of the check post or barrier or any other officer as specified under sub-section (2), or transport the goods without documents or without genuine documents, the officer not below the rank of Excise and Taxation Officer, shall, after affording such person-in-charge a reasonable opportunity of being heard, direct him to pay by way of penalty, an amount equal to ten percentum of the value of such goods.”.

**Amendment of section 44.**—In section 44 of the principal Act—

(a) for sub-section (1), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(1) The State Government shall by notification, establish an appellate tribunal consisting of a Chairperson for the proper discharge of the functions conferred on the tribunal by or under this Act.

(1A) The State Government may, by notification, appoint member(s) to the tribunal as it may deem fit for the discharge of functions conferred on the tribunal by or under this Act.”;

(b) for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(5) All cases coming before the tribunal shall be decided in accordance with the procedure as may be prescribed.”; and

(c) in sub-section (8), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that the cases of the State shall be represented before the tribunal by an officer not below the rank of Excise and Taxation Officer or by the Law Officer.”.

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 सितम्बर, 2009

**संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-21 / 2009-लेज.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-9-2009 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 20) को वर्ष 2009 के अधिनियम संख्यांक 15 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं ।

आदेश द्वारा,  
(अवतार चन्द डोगरा),  
सचिव ।

**हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन अधिनियम, 2009**

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 17 सितम्बर, 2009 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का अधिनियम संख्यांक 22) का और संशोधन करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

**1. संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) संशोधन अधिनियम, 2009 है।

**2. धारा 5 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश सरकारी स्थान और भूमि (बेदखली और किराया वसूली) अधिनियम, 1971 (1971 का 22) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'मूल अधिनियम' कहा गया है) की धारा 5 में -

(क) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के उपबन्धों के अधीन, कलक्टर धारा 4 के अधीन नोटिस जारी होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर बेदखली का आदेश करेगा, तथापि, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अवधि को तीन मास तक के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।” और

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधाराएं रखी जाएंगी, अर्थात् :—

“(2) यदि कोई व्यक्ति बेदखली के आदेश का, उपधारा (1) के अधीन इसके प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर पालन करने से इन्कार करता है या असफल रहता है तो कलक्टर या उस द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी उपर्युक्त वर्णित अवधि के अवसान के पन्द्रह दिन के पश्चात् उस व्यक्ति को बेदखल कर सकेगा और सरकारी स्थान का कब्जा ले सकेगा तथा उस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकेगा जो आवश्यक हो।

(3) कलक्टर, इस धारा के अधीन बेदखल व्यक्ति पर दस हजार रुपए तक या स्थान के बाजार मूल्य, जो भी उच्चतर हो, का जुर्माना अधिरोपित करेगा।”।

**3. धारा 7 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 7 में उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“परन्तु उपधारा (1) और (2) के अधीन प्रत्येक आदेश छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा तथापि कारणों को लिखित में अभिलिखित करके अवधि को तीन मास तक के लिए और बढ़ाया जा सकेगा।”।

**4. धारा 9 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 9 में उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“(4) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील आयुक्त द्वारा तीन मास की अवधि के भीतर निपटाई जाएगी।”।

**5. धारा 11 का संशोधन.**—मूल अधिनियम की धारा 11 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

“(1) यदि कोई व्यक्ति जिसे इस अधिनियम के अधीन किसी सरकारी स्थान से बेदखल किया गया हो स्थान को पुनः अपने अधिभोग में, ऐसे अधिभोग के लिए प्राधिकार के बिना लेता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा या स्थान के बाजार मूल्य के दुगुने से, जो भी उच्चतर हो, या दोनों से, दण्डनीय होगा।”।

-----

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**Act No. 15 of 2009**

**THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC PREMISES AND LAND (EVICTION AND RENT RECOVERY) AMENDMENT ACT, 2009**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 17TH SEPTEMBER, 2009)

AN

**ACT**

*further to amend the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 ( Act No. 22 of 1971).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of the Republic of India, as follows:—

**1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Act, 2009.

**2. Amendment of section 5.**—In section 5 of the Himachal Pradesh Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Act, 1971 (22 of 1971) (hereinafter referred to as the ‘principal Act’)—

(a) after sub-section (1), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that subject to the provisions of this Act or any rules made thereunder, the Collector shall make an order of eviction within a period of six months from the date of issuance of notice under section 4, however, the period may further be extended by three months for the reasons to be recorded in writing.”; and

(b) for sub-section (2), the following sub-sections shall be substituted, namely:—

“(2) If any person refuses or fails to comply with the order of eviction within fifteen days of the date of its publication under sub-section (1), the Collector or any other officer duly authorized by him in this behalf may evict that person, within fifteen days after expiry of the above mentioned period, and take possession of the public premises and may, for that purpose, use such force as may be necessary.

- (3) The Collector shall impose upon the person evicted under this section a fine upto ten thousand rupees or the market value of the premises whichever is higher.”.

**3. Amendment of section 7.**—In section 7 of the principal Act, after sub-section (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that every order under sub-sections (1) and (2) shall be made within a period of six months, however, the period may further be extended by three months for the reasons to be recorded in writing.”.

**4. Amendment of section 9.**—In section 9 of the principal Act, for sub-section (4), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(4) Every appeal under this section shall be disposed of by the Commissioner within a period of three months.”.

**5. Amendment of section 11.**—In section 11 of the principal Act, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) If any person who has been evicted from any public premises under this Act, again occupies the premises without authority for such occupation, he shall be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine which may extend to twenty thousand rupees or twice the market value of the premises, whichever is higher, or with both.”.

## विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 19 सितम्बर, 2009

**संख्या एल0एल0आर0-डी0(6)-16/2009-लेज.**—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 17-09-2009 को अनुमोदित हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) विधेयक, 2009 (2009 का विधेयक संख्यांक 9) को वर्ष 2009 के अधिनियम संख्यांक 13 के रूप में संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,  
अवतार चन्द डोगरा,  
सचिव।

हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009

धाराओं का क्रम

धारा :

1. संक्षिप्त नाम।
2. परिभाषाएं।

3. ऊर्जा के उपभोग या प्रदाय पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण।
4. विद्युत शुल्क का संग्रहण और संदाय।
5. अभिलेख और विवरणियां।
6. निरीक्षण अधिकारी।
7. कतिपय मामलों में शास्तिक शुल्क का संदत्त किया जाना।
8. शुल्क की वसूली।
9. शुल्क के असंदाय पर प्रदाय को काटने की शक्ति।
10. शास्तियां।
11. विद्युत शुल्क के संदाय से छूट देने की शक्ति।
12. निरीक्षण अधिकारियों का लोक सेवक होना।
13. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति।
14. सरकार की पूर्व मंजूरी।
15. नियम बनाने की शक्ति।
16. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।
17. निरसन और व्यावृत्तियां।

## 2009 का अधिनियम संख्यांक 13

### हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 17 सितम्बर, 2009 को यथाअनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश राज्य में विद्युत के उपभोग या प्रदाय पर विद्युत शुल्क के उद्ग्रहण के लिए उपबन्ध करने हेतु विधि पुनः अधिनियमित करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. **संक्षिप्त नाम.**—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 2009 है।

2. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "परिषद्" से निरसित किए गए विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 54) की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) "उपभोक्ता" से कोई व्यक्ति या स्थापन अभिप्रेत है, जो ऊर्जा का उपयोग या उपभोग करता है और जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट उपभोक्ताओं के प्रवर्ग भी हैं;

(ग) विद्युत के सम्बन्ध में "उपभोग" से किसी अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता द्वारा के.डब्ल्यू.एच. या के. वी. ए. एच. के रूप में अभिलिखित प्रति किलोवाट/के.वी.ए. विद्युत का उपभोग अभिप्रेत है;

- (घ) "ऊर्जा" से विद्युत ऊर्जा अभिप्रेत है;
- (ङ) "निरीक्षण अधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन इस रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (च) "मीटर" से एकीकृत करने वाले उपकरणों का सैट अभिप्रेत है, जिसे प्रदाय की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा या प्रदाय में अन्तर्विष्ट विद्युत ऊर्जा की मात्रा (परिमाण) को, दिए गए समय में मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसके अन्तर्गत होल करन्ट मीटर और मीटरिंग उपकरण जैसे कि आवश्यक वायरिंग और उपसाधनों सहित करन्ट ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर या पोटेन्शियल या वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी है;
- (छ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ज) "धारा" से इस अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;
- (झ) "राज्य सरकार" या "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
- (ञ) विद्युत के सम्बन्ध में "प्रदाय" से अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता को विद्युत का विक्रय अभिप्रेत है; और
- (त) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे जो विद्युत अधिनियम, 2003 या भारतीय विद्युत नियम, 1956 में उनके हैं।

**3. ऊर्जा के उपयोग या प्रदाय पर विद्युत शुल्क का उद्ग्रहण.—**(1) किसी भी स्रोत से उत्पादित ऊर्जा, जिसका परिषद्, किसी अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यापारी या विद्युत उत्पादन करने वाली कम्पनी द्वारा उपभोग किया गया है या जिसका परिषद्, ऐसे अनुज्ञप्तिधारी, व्यापारी या कम्पनी द्वारा उपभोक्ता को प्रदाय किया गया है, पर विद्युत शुल्क के नाम से शुल्क, निम्नलिखित रीति में उद्गृहीत किया जाएगा और राज्य सरकार को संदत्त किया जाएगा:—

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| (i) घरेलू उपभोक्ताओं से  | —तीन प्रतिशत की दर से,  |
| (ii) गैर-घरेलू गैर-वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से                     | —तीन प्रतिशत की दर से,  |
| (iii) कृषि/सिंचाई या सहबद्ध क्रियाकलाप प्रदाय के उपभोक्ताओं से | —दस प्रतिशत की दर से,   |
| (iv) वाणिज्यिक उपभोक्ताओं से                                   | —आठ प्रतिशत की दर से,   |
| (v) औद्योगिक उपभोक्ता,—  |                         |
| (क) लघु औद्योगिक उपभोक्ताओं से                                 | —नौ प्रतिशत की दर से,   |
| (ख) मध्यम दर्जे के और बड़े औद्योगिक उपभोक्ताओं से              | —तेरह प्रतिशत की दर से, |
| (vi) वाटर पम्पिंग सप्लाई उपभोक्ताओं से                         | —दस प्रतिशत की दर से,   |
| (vii) बल्क सप्लाई उपभोक्ताओं से                                | —दस प्रतिशत की दर से,   |

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| (viii) स्ट्रीट लाईटिंग सप्लाई उपभोक्ताओं से   | —दस प्रतिशत की दर से,    |
| (ix) टेम्परेरी मीटरड सप्लाई उपभोक्ताओं से   | —चार प्रतिशत की दर से,   |
| (x) उपरोक्त खण्ड (i) से (ix) के अन्तर्गत न आने वाले उपभोक्ताओं के अन्य प्रवर्गों से   | —दस प्रतिशत की दर से, और |
| (xi) डीजल जनरेटिंग सैटों द्वारा, (या किसी भी प्रकार की अन्य रीति द्वारा), ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण में प्रयोग हेतु या अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता के अपने उपभोग के लिए कॅपटिव/स्टैंडबाई हेतु, उत्पादित विद्युत ऊर्जा की दशा में, प्रति यूनिट विद्युत शुल्क। | — तीस पैसे की दर से:     |

परन्तु प्रत्येक प्रवर्ग के सामने वर्णित प्रतिशतता, केवल ऊर्जा प्रभागों (मीटर किराया, सेवा प्रभागों आदि को अपवर्जित करके) पर लागू होगी।

(2) धारा 3 की कोई भी बात, विद्युत के उपभोग या विक्रय के लिए लागू नहीं होगी जो,—

- (क) भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा उपभुक्त हो या भारत सरकार या भारतीय संघ के राज्य क्षेत्रों के भीतर अन्य सरकार (सरकारों) को, उस सरकार द्वारा या ऊर्जा सेक्टर में लगी हुई अन्य उपयोगिताओं द्वारा उपभोग हेतु या विक्रय हेतु, विक्रीत की गई हो; या
- (ख) भारत सरकार द्वारा किसी रेल के सन्निर्माण, रख-रखाव या चलाने (संचालन) में या उस रेल को चलाने (संचालन करने) वाली रेल कम्पनी द्वारा उपभुक्त हो या उस सरकार या ऐसी किसी रेल कम्पनी को किसी रेल के सन्निर्माण, रख-रखाव या चलाने (संचालन) हेतु उपभोग करने के लिए विक्रय की गई हो; या
- (ग) किसी अनुज्ञप्तिधारी या ऊर्जा का उत्पादन करने वाले उपभोक्ता द्वारा, उसके अपने उपभोग के लिए उपभुक्त हो; परन्तु जनरेटर की क्षमता दस किलोवाट से अधिक न हो।

(3) विद्युत शुल्क की संगणना के प्रयोजन के लिए धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना जारी होने के पश्चात्, मीटर द्वारा दर्शाई गई खपत, मीटर की प्रथम रीडिंग की तारीख के पश्चात् आरम्भ करते हुए गणना में ली जाएगी।

**4. विद्युत शुल्क का संग्रहण और संदाय.—**(1) राज्य सरकार का विद्युत शुल्क पर प्रथम प्रभार होगा और न तो परिषद् और न ही कोई अनुज्ञप्तिधारी, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना इस शुल्क का उपयोग किसी भी रकम, जो राज्य सरकार द्वारा परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी/या किसी अन्य अभिकरण को देय हो, की प्रतिपूर्ति स्वयं को करने के लिए करेगा।

(2) परिषद् या विद्युत का उपभोग करने वाले या उपभोग के लिए इसका प्रदाय करने वाले अनुज्ञप्तिधारी का यह कर्तव्य होगा कि वह अपनी खपत या प्रदाय के क्षेत्र के समस्त उपभोक्ताओं से विद्युत शुल्क का संदाय या संग्रहण, ऐसे प्ररूप में करे और राज्य सरकार को उसका संदाय तिमाही पर या ऐसी रीति में करे, जैसी विहित की जाए।

(3) अनुज्ञप्तिधारी या उपभोक्ता द्वारा जनरेटिंग सैटों, चाहे किसी भी रीति (ढंग) से, के माध्यम से, अपने उपभोग के लिए विद्युत ऊर्जा के आबद्ध (कॅपटिव) या तैयार (स्टैंडबाई) उत्पादन की दशा में विद्युत शुल्क, यदि कोई हो, सम्बद्ध उपभोक्ता द्वारा तिमाही पर, राज्य सरकार के पास विद्युत निरीक्षणालय के माध्यम से, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, सीधे जमा किया जाएगा।



**5. अभिलेख और विवरणियां।—**(1) यदि राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा निदेश दे, तो विद्युत का प्रदाय, क्रय, उत्पादन या पारेषण करने वाली परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी या कोई व्यक्ति, ऐसा अभिलेख, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में रखेगा, जैसी विहित की जाए, जिसमें निम्नलिखित दर्शित हो—

(क) अपने उपभोग के लिए अथवा किसी उपभोक्ता या अनुज्ञप्तिधारी को प्रदाय के लिए उत्पादित, पारेषित या प्राप्त विद्युत के यूनिट;

(ख) किसी उपभोक्ता को प्रदाय किए गए या उसके द्वारा उपभुक्त विद्युत के यूनिट;

(ग) उस पर देय विद्युत शुल्क की रकम और इस अधिनियम के अधीन उस द्वारा संदत्त या वसूल किया गया विद्युत शुल्क; और

(घ) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं।

(2) विद्युत का उत्पादन या क्रय करने वाली परिषद्, अनुज्ञप्तिधारी या कोई व्यक्ति, जिसे राज्य सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन ऐसा अभिलेख रखने के लिए निदेश दिया गया है, ऐसी विवरणियां, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में ऐसे प्राधिकारी (अॅथारिटी) को, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) के प्रयोजनों के लिए ऊर्जा की मात्रा, मुख्य विद्युत निरीक्षक द्वारा, ऐसी रीति में अभिनिश्चित की जाएगी, जैसी विहित की जाए।

**6. निरीक्षण अधिकारी।—**(1) राज्य सरकार, धारा 5 के अधीन रखे गए अभिलेख और विवरणियों के निरीक्षण के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा मुख्य विद्युत निरीक्षक तथा मुख्य विद्युत निरीक्षक की सहायता के लिए किसी अन्य अधिकारी को, निरीक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगी।

(2) निरीक्षण अधिकारी, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा, जैसी विहित की जाएं।

**7. कतिपय मामलों में शास्तिक शुल्क का दिया जाना।—**(1) यदि निरीक्षण अधिकारी की राय में, यथास्थिति, परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यवसायी या उत्पादन करने वाली कम्पनी या उपभोक्ता, शुल्क के संदाय की अपवंचना करता है या अपवंचन करने का प्रयास करता है या जानबूझकर लोप अथवा उपेक्षा करता है, चाहे मिथ्या अभिलेख रखकर या छलसाधन करके या मिथ्या विवरणियां प्रस्तुत करके या उपभुक्त ऊर्जा को छिपाकर या किसी अन्य साधन द्वारा, तो, यथास्थिति, परिषद्, अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यवसायी, उत्पादन करने वाली कम्पनी या उपभोक्ता इस अधिनियम के अधीन संदेय शुल्क के अतिरिक्त शास्ति के रूप में विद्युत शुल्क की राशि के चार गुणा से अनधिक, ऐसी रकम का संदाय करेगा, जो निरीक्षण अधिकारी द्वारा, इस सम्बन्ध में आदेश पारित करके अवधारित की जाए:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई भी शास्ति, यथास्थिति, परिषद्, अनुज्ञप्तिधारी, विद्युत व्यवसायी, उत्पादन करने वाली कम्पनी या उपभोक्ता को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसे प्राधिकारी को, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी फीस के संदाय पर होगी, जैसी विहित की जाए।

(3) उपधारा (2) के अधीन अपील में पारित कोई आदेश, विवाद के पक्षकारों पर अन्तिम और आबद्धकर होगा।

(4) इस धारा के अधीन किसी भी शास्ति के संदाय के लिए किया गया आदेश, इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, संस्थित किए जा सकने वाले या अधिरोपित किए जाने वाले किसी अभियोजन और अन्य शास्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

**8. शुल्क की वसूली.—**(1) इस अधिनियम के अधीन देय कोई भी विद्युत शुल्क या धारा 7 के अधीन अधिरोपित शास्ति, जो चाहे किसी उपभोक्ता द्वारा परिषद् को या वितरण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को, अथवा परिषद् या वितरण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी द्वारा राज्य सरकार को, असंदत्त रहती है, भू-राजस्व की बकाया के रूप में या राज्य सरकार द्वारा परिषद् या वितरण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी या ऐसे उपभोक्ता को संदेय रकमों में से कटौती द्वारा, वसूलीय होगी।

(2) जब किसी विद्युत शुल्क या शास्ति की रकम देय हो गई हो परन्तु संदत्त नहीं की गई हो, तो निरीक्षण अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन इस बाबत बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन, देय रकम की वसूली करने के लिए कलक्टर को आवेदन करेगा, मानो यह भू-राजस्व का बकाया हो।

(3) उपधारा (2) के अधीन किए गए आवेदन में निम्नलिखित विवरण होंगे—

- (i) व्यतिक्रमी का नाम और विवरण;
- (ii) बकाया की रकम, जिसकी वसूली अपेक्षित है; और
- (iii) परिस्थितियां, जिनके कारण आवेदन आवश्यक हुआ।

(4) आवेदन की प्राप्ति पर कलक्टर, हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अधीन रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करने की प्रक्रिया आरम्भ करेगा।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, परिषद् या किसी अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यवसायी या उत्पादन करने वाली कम्पनी की जंगम (चल) और स्थावर (अचल) सम्पत्ति, किसी भी न्यायालय की डिक्री या आदेश के निष्पादन में लिए जाने के लिए तब तक दायी नहीं होगी जब तक, यथास्थिति, परिषद् या अनुज्ञप्तिधारी या विद्युत व्यवसायी या उत्पादन करने वाली कम्पनी द्वारा संदेय विद्युत शुल्क, राज्य सरकार को संदत्त न कर दिया गया हो।

**स्पष्टीकरण.—**पद “कलक्टर” का वही अर्थ होगा जो हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 में उसका है।

**9. शुल्क के असंदाय पर प्रदाय को काटने की शक्ति.—**जहां उपभोक्ता उस विद्युत की बाबत, जिसका प्रदाय उसे किया गया है, उस द्वारा देय विद्युत शुल्क का संदाय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, परिषद् या विद्युत का प्रदाय करने वाला वितरण अनुज्ञप्तिधारी, कम से कम पन्द्रह दिन का लिखित में नोटिस देने के पश्चात्, ऐसे व्यक्ति के विद्युत प्रदाय को तब तक के लिए काट सकेगा जब तक सम्पूर्ण विद्युत शुल्क संदत्त नहीं कर दिया जाता।

**10. शास्तियां.—**यदि कोई व्यक्ति—

- (क) जिससे धारा 5 के अधीन अभिलेख रखने या विवरणियां प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है, उन्हें विहित प्ररूप या रीति में रखने या प्रस्तुत करने में असफल रहता है या ऐसी विवरणी प्रस्तुत करता है जो मिथ्या है, या
- (ख) किसी निरीक्षण अधिकारी को, इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के अधीन, उसकी शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यपालन में साशय बाधा पहुंचाता है, या
- (ग) इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन करता है,

तो वह ऐसा जुर्माना, जैसा विहित प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए, जो एक लाख रूपए से अधिक नहीं होगा, संदत्त करने के लिए दायी होगा।

**11. विद्युत शुल्क के संदाय से छूट देने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार, लोकहित में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अनुज्ञप्तिधारी, उपभोक्ता या व्यक्ति को, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्त के अधीन, जैसी ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, संपूर्ण विद्युत शुल्क या उसके भाग के संदाय से छूट प्रदान कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विद्युत शुल्क की दरों को, किसी एक समय में, धारा 3 के अधीन विनिर्दिष्ट दरों के पचास प्रतिशत से अधिक पुनरीक्षित नहीं कर सकेगी।

**12. निरीक्षण अधिकारियों का लोक सेवक होना.**—इस अधिनियम की धारा 6 के अधीन नियुक्त प्रत्येक निरीक्षण अधिकारी के बारे में, जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण में कोई कार्य कर रहा है या उसका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक है।

**13. इस अधिनियम के अधीन कार्य करने वाले व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति.**—इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां, किसी व्यक्ति के विरुद्ध संस्थित नहीं की जाएंगी।

**14. सरकार की पूर्व मंजूरी.**—इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए कोई अभियोजन, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना संस्थित नहीं किया जाएगा।

**15. नियम बनाने की शक्ति.**—(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

- (क) धारा 3 और 4 के अधीन विद्युत शुल्क के संदाय तथा संग्रहण की रीति;
- (ख) प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन अभिलेख अनुरक्षित रखा जाएगा;
- (ग) धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) के अधीन विशिष्टियों का विहित किया जाना;
- (घ) विवरणियां प्रस्तुत करने की रीति और प्राधिकारी (अथॉरिटी), जिसे धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इन्हें प्रस्तुत किया जाना है;
- (ङ) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां और पालन किए जाने वाले कर्तव्य;
- (च) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकारी (अथॉरिटी), जिसे अपील की जाएगी, अवधि जिसके भीतर अपील की जाएगी और ऐसी अपील को दाखिल करने के लिए फीस;
- (छ) प्राधिकारी (अथॉरिटी), जिसके द्वारा धारा 10 के अधीन जुर्माना अवधारित किया जाना है ;और
- (ज) कोई अन्य मामला, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित है या जिसे विहित किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के, जिसमें वह इस प्रकार रखा

गया है, या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व, विधान सभा नियम में कोई परिवर्तन करती है, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा यह विनिश्चय करती है या यह निर्णय लेती है कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**16. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति.**—(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

**17. निरसन और व्यावृत्तियां.**—(1) हिमाचल प्रदेश विद्युत (शुल्क) अधिनियम, 1975 (1975 का 11) का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी की गई या किए जाने के लिए आशयित कोई बात या कार्रवाई, उद्गृहीत किया गया विद्युत शुल्क, बनाया गया नियम, जारी की गई अधिसूचना, किया गया निरीक्षण, किया गया आदेश या जारी किया गया नोटिस, जहां तक यह इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो, प्रवृत्त बना रहेगा और इस अधिनियम के उपबन्धों द्वारा या के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई या की गई समझी जाएगी, मानो यह अधिनियम, उस तारीख जिसको ऐसी बात या ऐसी कार्रवाई की गई थी, प्रवृत्त था, जब तक इसे इस अधिनियम द्वारा या के अधीन अधिक्रान्त नहीं कर दिया जाता और इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन देय विद्युत शुल्क और अन्य रकम संगृहीत की जा सकेगी मानो यह इस अधिनियम के अधीन प्रोद्भूत हुई हो।

#### *AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

### **THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY ( DUTY) ACT, 2009**

#### **ARRANGEMENT OF SECTIONS**

##### **Sections :**

1. Short title.
2. Definitions.
3. Levy of electricity duty on consumption or supply of energy.
4. Collection and payment of electricity duty.
5. Records and returns.
6. Inspecting Officers.
7. Penal duty to be paid in certain cases.
8. Recovery of duty.
9. Power to disconnect supply for non payment of duty.
10. Penalties.
11. Power to exempt from payment of electricity duty.

12. Inspecting Officers to be public servant.
13. Indemnity to persons acting under this Act.
14. Previous sanction of the Government.
15. Power to make rules.
16. Power to remove difficulties.
17. Repeal and savings

**Act No. 13 of 2009**

## **THE HIMACHAL PRADESH ELECTRICITY (DUTY) ACT, 2009**

**( AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 17TH SEPTEMBER, 2009)**

AN

### **ACT**

*to re-enact the law to provide for the levy of electricity duty on consumption or supply of electricity in the State of Himachal Pradesh and matters connected therewith or incidental thereto.*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixtieth Year of Republic of India as follows :-

**1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 2009.

**2. Definitions.**—In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Board" means the Himachal Pradesh State Electricity Board constituted under sub-section (1) of section 5 of the repealed Electricity (Supply) Act, 1948 (Act No. 54 of 1948);
- (b) "consumer" means any person or establishment who uses or consumes energy and includes categories of consumers specified under section 3 of this Act ;
- (c) "consumption" in relation to electricity means electrical consumption per Kilowatt/KVA recorded as KWh or KVAh. by a licensee or consumer;
- (d) "energy" means electric energy;
- (e) "Inspecting Officer" means a person appointed as such by the State Government under sub-section (1) of section 6;
- (f) "meter" means a set of integrating instruments used to measure the amount of electrical energy supplied or the quantity of electrical energy contained in the supply, in a given time, which include whole current meter and metering equipment such as current transformer, capacitor voltage transformer or potential or voltage transformer with necessary wiring and accessories;
- (g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

- (h) “section” means section of this Act;
- (i) “State Government” or “Government” means the Government of Himachal Pradesh;
- (j) “supply” in relation to electricity means the sale of electricity to a licensee or consumer; and
- (k) the words and expressions used in this Act, but not defined shall have the meanings as assigned to them in the Electricity Act, 2003 or the Indian Electricity Rules, 1956.

**3. Levy of electricity duty on consumption or supply of energy.**—(1) There shall be levied and paid to the State Government on the energy, generated from any source, consumed by the Board, any licensee, electricity trader or generating company or supplied by the Board, such licensee, trader or company to the consumer, a duty to be called the electricity duty, in the following manner, namely:-

- |   |               |
|---|---------------|
| (i) domestic consumers  | - @ 3%,       |
| (ii) non domestic non commercial consumers  | - @ 3%,       |
| (iii) agricultural/irrigation or allied activities supply consumers   | - @ 10%,      |
| (iv) commercial consumers   | - @ 8%        |
| (v) industrial consumers,—  |               |
| (a) small industrial consumers  | - @ 9%,       |
| (b) medium and large industrial consumers   | - @ 13%,      |
| (vi) water pumping supply consumers   | - @ 10%,      |
| (vii) bulk supply consumers   | - @ 10%,      |
| (viii) street lighting supply consumers   | - @ 10%,      |
| (ix) temporary metered supply consumers   | - @ 4%,       |
| (x) other category of consumers not covered under clauses (i) to (ix) above   | - @ 10% and , |
| (xi) In case of electrical energy generated by diesel generating sets (or by what so ever mode) for use of construction of power projects or captive/standby for own consumption by the licensee or consumer, electricity duty per unit | -@ 30 paise:  |

Provided that the percentage mentioned against each categories shall be applicable on energy charges only (excluding meter rent, service charges etc.).

(2) Nothing in section 3 shall apply to the consumption or sale of electricity which is-----

- (a) consumed by the Government of India, State Government or sold to the Government of India or other Government(s) within the territories of Indian Union for consumption or sale by that Government or other utilities engaged in power sector; or
- (b) consumed in the construction, maintenance or operation of any railway by the Government of India or a railway company operating that railway, or sold to that Government or any such railway company for consumption in the construction, maintenance or operation of any railway; or
- (c) consumed by a licensee or by consumer generating energy for their own consumption; provided the capacity of generator does not exceed 10 KW.

(3) For the purpose of computing the electricity duty, the consumption shown by the meter, starting after the first meter reading date, after the issuance of the notification under sub-section (1) of section 3 shall be taken into account.

**4. Collection and payment of electricity duty.**—(1) The State Government shall have the first charge on the electricity duty and neither the Board nor any licensee shall, without the previous sanction of the State Government, utilize this duty to reimburse itself for any amount, which the State Government may owe to the Board or the licensee/ or any other agency.

(2) It shall be the duty of the Board or the licensee consuming or supplying electricity for consumption to pay or collect the electricity duty from all the consumers in its area of consumption or supply in such form and pay the same to the State Government quarterly or in such manner, as may be prescribed.

(3) In case of captive or standby generation of electrical energy for own consumption through generating sets, by whatsoever mode, by the licensee or consumer, electricity duty, if any, shall be deposited quarterly by the concerned consumer directly to the State Government through Electrical Inspectorate in such manner as may be prescribed.

**5. Records and returns.**—(1) If the State Government so directs, by a general or special order, the Board or a licensee or a person supplying, purchasing, generating or transmitting electricity, shall maintain such record, in such form and in such manner, as may be prescribed, showing -

- (a) the units of electricity generated, transmitted or received for own consumption or for supply to any consumer or licensee;
- (b) the units of electricity supplied to any consumer or consumed by it or him;
- (c) the amount of electricity duty payable thereon and the electricity duty paid or recovered by him, under this Act; and
- (d) such other particulars, as may be prescribed.

(2) The Board, the licensee or the person generating or purchasing electricity, directed by the State Government under sub-section (1) to maintain records, shall submit such returns in such form and in such manner and to such authority, as may be prescribed.

(3) For the purposes of clauses (a) and (b) of sub-section (1), the amount of energy shall be ascertained by the Chief Electrical Inspector in such manner as may be prescribed.

**6. Inspecting Officers.**—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, appoint Chief Electrical Inspector and any other officer, to assist the Chief Electrical Inspector, to be the Inspecting Officer to inspect records and returns maintained under section 5.

(2) The Inspecting Officer shall perform such duties and exercise such powers, as may be prescribed, for the purpose of carrying into effect the provisions of this Act and the rules made thereunder.

**7. Penal duty to be paid in certain case.**—(1) If in the opinion of the Inspecting Officer, the Board or the licensee or the electricity trader or the generating company or the consumer, as the case may be, evades or attempts to evade or wilfully omits or neglects the payment of duty, whether by maintaining or manipulating false records or by submitting false returns or by concealing the energy consumed or by any other means, the Board, the licensee, the electricity trader, the generating company or the consumer, as the case may be, shall pay by way of penalty, in addition to the duty payable under this Act, a sum not exceeding four times the amount of the electricity duty, as may be determined by the Inspecting Officer, by passing an order in this regard:

Provided that no penalty under this sub-section shall be imposed without affording a reasonable opportunity of being heard to the Board, the licensee, the electricity trader, the generating company or the consumer, as the case may be.

(2) An appeal shall lie against an order passed under sub-section (1) to such authority within such period and on payment of such fee, as may be prescribed.

(3) An order passed on appeal under sub-section(2), shall be final and binding on the parties to the dispute.

(4) An order for the payment of any penalty, made under this section, shall be without prejudice to any prosecution and other penalty which may be instituted or imposed, as the case may be, under this Act.

**8. Recovery of duty.**—(1) Any electricity duty due under this Act, or penalty imposed under section 7, which remains unpaid, whether by a consumer to the Board or to the distributing licensee, or by the Board or the distributing licensee to the State Government, shall be recoverable as an arrears of land revenue or by deduction from the amounts payable by the State Government to the Board or the distributing licensee or such consumer.

(2) When any sum of electricity duty or penalty has fallen due, but has not been paid, the Inspecting Officer may, subject to the provisions of the rules made in this behalf under this Act, make an application to the Collector to recover the sum due as if it were an arrears of land revenue.

(3) An application made under sub-section (2), shall state—

- (i) the name and description of the defaulter,
- (ii) the amount of arrear of which recovery is required; and
- (iii) the circumstances which have made the application necessary.



(4) On receipt of the application, the Collector shall proceed to recover the amount as arrears of land revenue under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

(5) Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the movable and immovable property of the Board or any licensee, or electricity trader or a generating company shall not be liable to be taken in execution of a decree or order of any court, until the electricity duty payable by the Board or the licensee or the electricity trader or the generating company, as the case may be, to the State Government has been paid.

**Explanation.**—The expression “Collector” shall have the same meaning as assigned to it under the Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

**9. Power to disconnect supply for non payment of duty.**—Where the consumer fails to pay the electricity duty due from him in respect of the electricity supplied, the Board or the distribution licensee supplying electricity, as the case may be, may, after giving not less than fifteen days notice in writing, cut off the electricity supply to such person, until the entire electricity duty is paid.

**10. Penalties.**—If any person-

- (a) required under section 5 to maintain records or to submit returns, fails to keep or submit the same in the prescribed form or manner or submit a return which is false, or
- (b) intentionally obstructs an Inspecting Officer in the exercise of his powers and discharge of his duties under this Act and the rules made thereunder, or
- (c) contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder;

shall be liable to pay fine, not exceeding one lac rupees, as may be determined by the prescribed authority.

**11. Power to exempt from payment of electricity duty.**—(1) The State Government may, in public interest, by notification in the Official Gazette, exempt any licensee, consumer or person from the payment of the whole or part of the electricity duty for such period and subject to such conditions as may be specified in such notification.

(2) The State Government may, by notification, revise the rates of electricity duty not exceeding 50% at any one time, of the rates specified under section 3.

**12. Inspecting Officers to be public servants.**—Every Inspecting Officer, appointed under section 6 of this Act, shall be deemed, while acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servant within the meaning of section 21 of Indian Penal Code, 1860.

**13. Indemnity to persons acting under this Act.**—No suit, prosecution or other legal proceedings shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intended to be done under this Act.

**14. Previous sanction of the Government.**—No prosecution for any offence, punishable under this Act shall be instituted, except with the previous sanction of the State Government.

**15. Power to make rules.**—(1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying into effect the provisions of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

- (a) the manner of payment and collection of electricity duty under sections 3 and 4;
- (b) the form and manner in which record shall be maintained under sub-section (1) of section 5;
- (c) prescription of particulars under clause (d) of sub-section (1) of section 5;
- (d) the manner of submitting the returns and the authority to whom these are to be submitted under sub-section (2) of section 5;
- (e) the powers and duties to be exercised and performed by the Inspecting Officers under sub-section (2) of section 6;
- (f) the authority to whom appeal shall lie, the period within which appeal shall lie and the fee for filing such appeal under sub-section (2) of section 7;
- (g) the authority by whom the fine is to be determined under section 10; and
- (h) any other matter required to be prescribed or which may be prescribed by or under this Act.

(3) Every rule made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly while it is in session for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the successive sessions as aforesaid, the House agrees in making any modification in the rule or the House agrees that the rule should not be made, the rule shall, thereafter, have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

**16. Power to remove difficulties.**—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

(2) Every order made under this section, shall be laid, as soon as after it is made, before the State Legislative Assembly:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of a period of two years from the date of commencement of this Act.

**17. Repeal and savings.**—(1) The Himachal Pradesh Electricity (Duty) Act, 1975 (11 of 1975) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken or purported to have been done or taken, any electricity duty levied, any rule, notification, inspection, order or notice made or issued, shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, continue to be in force and be deemed to have been done or taken or made in exercise of the powers conferred by or under the provisions of this Act as if this Act was in force on the date on which such thing was done or such action was taken unless and until it is superseded by or under this Act and the electricity duty and other amount due under the Act, so repealed, may be collected as if they have accrued under this Act.

**कृषि विभाग****अधिसूचना**

शिमला -2, 7 सितम्बर, 2009

**संख्या कृषि-ए(3)-3/2008.**—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग में चाय रसानिज्ञ, वर्ग-II (अराजपत्रित), के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध-“क” के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती है, अर्थात् :—

**1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, चाय रसानिज्ञ, वर्ग-II (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है ।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

**2. निरसन और व्यावृत्तियां.**—(i) अधिसूचना संख्या उद्योग-II (ख)-2-14/95 तारीख 16-12-1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग, चाय रसानिज्ञ, वर्ग-III (अराजपत्रित), भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1997 का एतद्वारा निरसन किया जाता है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त उप-नियम(i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्यवाई इन नियमों के अधीन विधिमन्य रूप से की गई समझी जाएगी ।

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
सचिव ।

उपाबन्ध — “ क ”

हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग, में चाय रसानिज्ञ, वर्ग-II (अराजपत्रित), के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. पद का नाम.—चाय रसानिज्ञ ।

2. पदों की संख्या.—2 (दो) ।

3. वर्गीकरण.—वर्ग-II (अराजपत्रित) ।

4. वेतनमान.—6400-200-7000-220-8100-275-10300-340-10640 रुपये ।

5. चयन अथवा अचयन पद.—चयन ।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु.—लागू नहीं ।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हता.—लागू नहीं ।

**8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं.—**लागू नहीं ।

**9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—**दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें ।

**10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता.—**शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा ।

**11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा.—**कनिष्ठ चाय रसानिज्ञों में से प्रोन्नति द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :—

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने-अपने प्रवर्ग/पद/कांडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पुर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा/समझे जाएंगे ।

**स्पष्टीकरण.—**अन्तिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नौन-टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1972 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इसके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स-सर्विसमैन (रिजर्वेशन आफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसिज) रूलज, 1985 के नियम-3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों ।

2. इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी ।

**12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.—**विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उस द्वारा नामर्दिष्ट सदस्य द्वारा की जाएगी ।

13. **भर्ती करने में जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.**—जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो ।

14. **सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.**—लागू नहीं ।

15. **सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.**—लागू नहीं ।

16. **आरक्षण.**—सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बावत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी ।

17. **विभागीय परीक्षा.**—लागू नहीं ।

18. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समाचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पदों की बावत, शिथिल कर सकेगी ।

[Authoritative English text of Government Notification No. Agr.-A(3)-/2008, dated 07-09-2009 as required under Article 348 (3) of the Constitution of India].

## AGRICULTURE DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 07th September, 2009*

**No. Agr.-A(3)-3/2008.**—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the H.P. Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Tea Chemist Class-II ( Non-Gazetted) in the Department of Agriculture, HP as per Annexure-A attached to this notification, namely :—

**1. Short title and Commencement.**—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Department of Agriculture, Tea Chemist, Class-II (Non-Gazetted), Recruitment & Promotion Rules, 2009.

(ii) These rules shall come into force from the date of their publication in Rajpatra, HP.

**2. Repeal and Savings.**—(i) The Himachal Pradesh Department of Industries, Tea Chemist class-III (Non-Gazetted) R&P Rules, 1997 notified vide notification No. Udyog.II(Kha)2-14/95 dated 16-12-97 are hereby repealed.

(ii) Notwithstanding such repeal any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(i) supra shall be deemed to have been validly made, done or taken under these rules.

By order,  
Sd/-  
Secretary.

**RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF TEA CHEMIST  
(CLASS-II- NON-GAZETTED) IN THE DEPARTMENT OF AGRICULTURE,  
HIMACHAL PRADESH**

1. **Name of the post.**—Tea Chemist
2. **Numbers of posts.**—2 (Two)
3. **Classification.**—Class-II ( Non-Gazetted)
4. **Scale of pay.**—Rs.6400-200- 7000-220-8100-275-10300-340-10640
5. **Whether selection post or Non-Selection post.**— Selection
6. **Age for direct recruitment.**—Not applicable.
7. **Minimum Education and other qualification required for direct recruits.**—Not applicable.
8. **Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees.**—Not applicable.
9. **Period of probation, if any.**—Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10. **Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.**—100% by promotion.
11. **In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion/deputation/ transfer is to be made.**—By promotion from amongst Jr. Tea Chemist having 5 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered in the grade.

(1) In all cases of promotion, the continuous adhoc services rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P rules; provided that, in all cases where a junior person become eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him in the respective category post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration;

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P rules for the post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

**Explanation.**—The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservations of vacancies in Himachal State Non-Technical Services) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provision of Rule-3 of the Ex-servicemen (Reservations of vacancies in Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

Similarly in all cases of confirmation continuous *adhoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such posts shall be taken into account towards the length of service, if the *adhoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provisions of R&P rules.

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

**12. If a departmental promotion committee, exists, what is its composition.**—DPC to be presided over by the Chairman, HP Public Service Commission or a member thereof to be nominated by him.

**13. Circumstances under which the HP PSC is to be consulted in making recruitments.**—As required under the Law.

**14. Essential requirement for a direct recruitment.**—Not applicable.

**15. Selection for appointment to post by direct recruitment.**—Not applicable.

**16. Reservation.**—The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Caste/Scheduled Tribes/Other Backward Classes/other categories of persons issued by the HP Government from time to time.

**17. Departmental Examination.**—Not applicable.

**18. Power to relax.**—Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by order, for reasons, to be recorded in writing and in consultation with the HP PSC, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

---

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचनाएं

शिमला, शिमला-171002, 14 सितम्बर, 2009

**संख्या सिंचाई 11-37/2009 कांगड़ा.**—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल भगलाहड़, मौजा ज्वाली,

तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में मध्यम सिंचाई परियोजना सिद्धाथा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राजपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे ।

### विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	मौजा/महाल	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर मीटर
कांगड़ा	ज्वाली	ज्वाली/भगलाहड़	38/2	0-02-04
			39/2	0-01-20
			46/2	0-01-32
			47/2	0-01-24
			49/2	0-01-68
			50/2	0-01-50
			51/2	0-01-32
			52/1	0-01-12
			53/2	0-00-96
			61/1	0-02-97
			62/1	0-01-88
			63/1	0-01-80
			Kitas-12	0-19-03

शिमला, शिमला-171002, 14 सितम्बर, 2009

**संख्या सिंचाई 11-39/2009 कांगड़ा.**—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल पपाहण, मौजा चलबाड़ा, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में मध्यम सिंचाई परियोजना सिद्धाथा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमत: सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।



4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राजपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

### विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	मौजा / महाल	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर मीटर
कांगड़ा	ज्वाली	चलबाड़ा / पपाहण	72/1	0-02-56
			70/1	0-02-23
			76/1	0-05-72
			38/1/1	0-02-64
			37/4/1	0-03-00
			33/1/1	0-00-07
			33/3/1	0-02-64
			30/2/2	0-00-95
			30/3/2	0-01-00
			30/4/2	0-01-00
			30/5/2	0-01-20
			4/1	0-04-08
			126/2	0-02-50
			119/2	0-03-53
			115/1	0-02-08
			116/1	0-00-21
			117/1	0-02-38
			97/1	0-01-64
			Kitas-18	0-39-43

शिमला, शिमला-171002, 14 सितम्बर, 2009

**संख्या सिंचाई 11-43/2009 कांगड़ा.**—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल ढन, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में मध्यम सिंचाई परियोजना सिद्धाथा के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अर्न्तगत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राजपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

## विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	मौजा/महाल	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर में
कांगड़ा	ज्वाली	ज्वाली-ढन	442/1	0-02-83
			501/1	0-02-09
			502/1	0-02-59
			1960/879	0-04-05
			1961/879/2	0-00-69
			878/1	0-00-35
			877/1	0-00-72
			875/1	0-00-60
			873/1	0-05-25
			863/1	0-01-28
			872/1	0-00-71
			639/1	0-00-90
			640/2	0-01-05
			641/2	0-00-87
			656/1	0-00-67
			657/1	0-00-95
			658/1	0-01-43
			753/1	0-00-30
			754/1	0-00-44
			756/1	0-02-37
			755/1/1	0-00-63
			758/1	0-01-16
			775/1	0-00-70
			774/1	0-02-22
			770/1	0-00-66
			771/1	0-00-42
			769/1	0-00-51
			762/1	0-00-48
			Kitas-28	0-36-92

शिमला, शिमला-171002, 17 सितम्बर, 2009

**संख्या सिंचाई 11-38/2009 कांगड़ा.**—यतः राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन के लिए नामतः महाल खरोटा, मौजा ज्वाली, तहसील ज्वाली, जिला कांगड़ा में मध्यम सिंचाई परियोजना सिद्धांश के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन अपेक्षित है ।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को जो इस से सम्बन्धित हैं, या हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भूमि-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है ।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने तथा सर्वेक्षण करने और उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः सभी अन्य कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं ।

4. अत्याधिक आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुये राजपाल उक्त अधिनियम की धारा-17 की उपधारा-4 के अधीन यह भी निर्देश देते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा-5 ए के उपबन्ध इस मामले में लागू नहीं होंगे।

### विस्तृत विवरणी

जिला	तहसील	मौजा/महाल	खसरा नम्बर	क्षेत्र हैक्टेयर मीटर
कांगड़ा	ज्वाली	खरोटा/ज्वाली	1015/1	0-01-26
			1019/1	0-01-54
			1031/1	0-06-20
			1032/1	0-02-95
			1041	0-02-19
			1322/1046/2/1	0-05-29
			1056/1	0-01-70
			1077/3	0-06-50
			1104/2	0-01-47
			1105/1	0-00-55
			1101/1	0-01-23
			1100/2	0-04-60
			1116	0-02-26
			1129/2	0-01-67
			1122/1	0-03-25
			714/1	0-02-48
			715/1	0-03-94
			1063/2	0-01-17
			1132/2	0-01-55
			1301/1133/1	0-01-40
			1302/1133/2	0-02-04
			1139/2	0-01-18
			1142/1	0-01-65
			1143/1	0-01-02
			1151/1	0-02-07
			1385/1155/1	0-00-55
			1384/1155/1	0-00-70
			1439/1156	0-03-20
			1389/1159/1	0-01-84
			1162/2	0-02-35
			1184/1	0-01-85
			1186/1	0-02-01
			Kitas-32	0-71-37

आदेश द्वारा,  
हस्ताक्षरित/—  
प्रधान सचिव।

**LAW DEPARTMENT****NOTIFICATION***Shimla-2, the 11th September, 2009*

**No. LLR-B (14)-2/2006.**—In supersession of this Department earlier Notification of even No. dated 5-4-2006 and in exercise of the powers conferred by Section 6(2)(b) of the Legal Services Authorities Act, 1987, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Hon'ble Chief Justice of High Court of Himachal Pradesh is pleased to nominate Hon'ble Mr. Justice R.B. Misra as Executive Chairman of the H.P. State Legal Services Authority with immediate effect.

By Order,

**A.C. DOGRA,**  
*L.R.-cum-Secretary.*